

कुलसचिव के पत्र से कालेज पूधानाचार्य असंतुष्ट

यूजीसी के कड़े रुख के बाद दबाव में विश्वविद्यालय प्रशासन डीयू ने वेबसाइट पर एफवाईयूपी के स्थान पर लिखा यूजी राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के चार वर्षीय पाठ्यक्रम पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कड़े रुख के बाद डीयू प्रशासन भारी दबाव में है। कालेज प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद डीयू पर दबाव बढ़ गया है। कालेज एसोसिएशन द्वारा डीयू और यूजीसी के बीच दाखिला संबंधी दिशा निर्देश को लेकर विरोधाभास की बात सामने आने पर आनन-फानन में डीयू की कुलसचिव ने कालेजों को यूजीसी द्वारा और जून को भेजे गए पत्र को ही बढ़ा दिया है। इसमें डीयू की तरफ से अतिरिक्त आदेश नहीं दिया है। इस पत्र से डीयू के कालेजों से कई प्रिंसिपल असंतुष्ट हैं। प्रिंसिपलों का कहना है कि यह

पत्र भ्रामक है और इसमें डीयू की तरफ से न कोई आदेश है और न ही कोई पक्ष। 1 कालेजों के प्रिंसिपल को सोमवार को लिखे पत्र में कुलसचिव ने लिखा है, मुझे यूजीसी के सचिव से दिनांक 22 जून, 2014 के आदेश से महाविद्यालयों को भेजे गए सम-संख्यक और सम दिनांकित पत्र को प्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है जो स्वतः स्पष्ट है। इस संबंध में कालेजों के प्रिंसिपलों का कहना है कि इस पत्र से कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे समय में डीयू को स्पष्ट रुख अख्तियार करना चाहिए। 1 इधर, सोमवार की दोपहर को डीयू की वेबसाइट से चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) स्टेटस की जगह स्नातक पाठ्यक्रम (यूजी) लगा दिया है। हालांकि, वेबसाइट के अन्य पेज पर यह बदलाव नहीं किया गया है।

कड़े फैसलों की मजबूरी संसद के बजट सत्र की तिथियों की घोषणा के साथ ही आम जनता की रेल बजट और आम बजट से उम्मीदें बढ़ जाना स्वाभाविक हैं। महंगाई से त्रस्त जनता यह चाहेगी कि बजट घोषणाएं उसके लिए कोई राहत की खबर लेकर आएँ, लेकिन कटु सच्चाई यह है कि मौजूदा आर्थिक हालात में सरकार चाहकर भी जनता को राहत देने की स्थिति में नहीं। यह सही है कि सरकार तेजी से काम करने के साथ बिगड़ी चीजों को बनाने के लिए अतिरिक्त श्रम कर रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वह आर्थिक हालत सुधारने के साथ जनता को कोई उल्लेखनीय रियायत-राहत दे सकेगी। ऐसा इसलिए और भी है, क्योंकि हर दिन यह सामने आ रहा है कि पिछली सरकार ने किस तरह देश का बेड़ा गर्क कर रखा था। ऐसा लगता है कि मनमोहन सरकार ने आम चुनावों के बहुत पहले से ही काम करना बंद कर दिया था। निःसंदेह पिछली सरकार को कोसने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन देश के सामने यह आना ही चाहिए कि संपूर्ण शासन ने किस तरह हालात बेकाबू हो

जाने दिए। आर्थिक मोर्चे पर दुर्दशा की तस्वीर उजागर करके ही मोदी सरकार कड़े फैसलों के औचित्य को सिद्ध करने में सक्षम हो सकेगी। पिछले दिनों रेल किराये-भाड़े में वृद्धि के फैसले से जनता को इसलिए और अधिक झटका लगा, क्योंकि सरकार ने यह फैसला लेने के पहले न तो कोई भूमिका बनाई और न ही जनता को यह बताने की जरूरत समझी कि भारतीय रेल किस तरह कंगाली की हालत में पहुँच चुकी है। अगर रेलवे की खस्ताहाल स्थिति और उसके जरिये की गई राजनीति को बयान करने के बाद रेल किराये-भाड़े में वृद्धि की घोषणा की जाती तो शायद आम जनता की प्रतिक्रिया कुछ भिन्न या फिर कम तीखी होती। 1 यह समय की मांग है कि सरकार तरक्की की रफ्तार बढ़ाने, रोजगार के अवसरों को पैदा करने और घाटे वाली अर्थव्यवस्था से उबरने के जो तमाम उपाय कर रही है उनके बारे में जनता को अवगत कराती चले। पिछले 20-25 दिनों में केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में अनेक फैसले लिए गए हैं। इनमें से कुछ फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं और अर्थव्यवस्था को

गति देने के साथ आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले भी हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आम जनता इन फैसलों और उनसे होने वाले लाभों के बारे में पूरी तरह परिचित है। इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि रेल बजट और आम बजट की तैयारियों के साथ ही सरकार की ओर से यह बताया जाए कि उसने क्या कुछ कर लिया है और क्या कुछ करने जा रही है? उसकी ओर से ऐसी बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं जो जनता को दिलासा दें। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ आम जनता की बेसब्री बढ़ती चली जा रही है। वह उन तमाम वायदों को भूली नहीं है जो मोदी और उनके साथियों ने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे। यह सही है कि चुनाव घोषणापत्र और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिये जो एक उजली तस्वीर दिखाई गई उसे आनन-फानन अथवा बजट के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता में भरोसा पैदा करने का काम तो किया ही जा सकता है। यह आवश्यक है कि कड़वी गोली की बातों के साथ ही मरहम लगाने की भी

उच्च शिक्षा की समस्या

पछिले दनियों एक अखबार में एक काटरून छपा था, जसमें लंबे समय से बीमार एक ऐसा मरीज अस्पताल के बसितर पर पड़ा हुआ था जससे बड़े-बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। ऊपर लिखा था कि शायद इसे अब 'तुलसी' का काढ़ा ही ठीक कर पाए। यह मरीज और कोई नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था थी और इशारा नई मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की ओर था, जो पहले तुलसी के नाम से टेलीविजन पर प्रसिद्ध रही थीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था की चतुर्दिक समस्याओं में से उच्च शिक्षा की समस्या की तह में जाना ज्यादा जरूरी है, जो किसी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होती है और जो वर्तमान राजग सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकता भी है।

शिक्षा में सबसे अहम भूमिका होती है शिक्षकों की, जिन पर देश का भविष्य कहे जाने वाले विद्यार्थियों की 30-35 पीढ़ियों की ज़िम्मेदारी होती है। अगर शिक्षक ही योग्य, परश्रमी, समर्पित और गुणवत्तायुक्त से युक्त न हो तो विद्यार्थी और देश का हश्र समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रथम सार्वजनिक भाषण में ही इसकी गंभीरता को समझते हुए कहा कि हमें श्रेष्ठ शिक्षक तैयार करने होंगे। वर्तमान में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों, लेक्चरर की न्युक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता पीएचडी होना या केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। कई राज्यों में तो राज्य द्वारा आयोजित राज्य योग्यता परीक्षा (सूलेट) पास होना ही काफी है। बताते चलें कि नेट की परीक्षा में जहां कई खामियां हैं वहीं सूलेट का स्तर तो काफी नमून होता है। उधर पीएचडी अनेक विश्वविद्यालयों में

जस तरह से हो रही है, वह भी सोचने का विषय है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि पीएचडी किसी विषय के किसी एक पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, जबकि नेट जैसी परीक्षा उस विषय के बारे में एक समग्र ज्ञान का परीक्षण व परीचयक है। सहायक प्राध्यापकों की न्युक्ति के लिए एकमात्र अर्हता नेट होना चाहिए। साथ ही नेट के वर्तमान प्रारूप में सुधार करते हुए सरिफ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अतिरिक्त वर्णनात्मक सवाल भी पूछे जाने चाहिए। शिक्षकों से संबंधित समस्या का परिमाणात्मक पक्ष भी है। विभिन्न कॉलेज, विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भारी कमी है, हजारों की तादाद में रिक्तियां सालों से लंबित हैं। शिक्षण कार्य जैसे-तैसे घसीटा जा रहा है। राज्यों में स्थिति तो बहुत ज्यादा ही खराब है। यथाशीघ्र इन रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ नवीनतम ज्ञान शोध और तकनीक आदि से शिक्षकों के सतत आधुनिकीकरण के लिए एक कारगर नीति बिनाई जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीयों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। विभिन्न अमेरिकी विश्व-विद्यालयों में पढ़ाने के दौरान मैंने अनुभव किया कि वहां काम कर रहे अनेक भारतीय प्राध्यापक और रिसर्चर स्थायी या अस्थायी रूप से अपने स्वदेश में आकर काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार, यूजीसी और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की लालफीताशाही और उदासीनता के कारण हम इन गुणवत्ता-पूर्ण लोगों से फायदा उठाने से महरूम हैं। समस्या का दूसरा पहलू शिक्षा के प्रारूप से जुड़ा है। हमारी उच्च शिक्षा अभी भी मैकाले सिद्धिरोम से ग्रस्त है, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी राज में

रेलवे स्टेशन पर दलित का दौरा पड़ने से हेड कांस्टेबल की मौत

जासं, फरीदाबाद : दिल्ली में मल्लि लावारसि बच्चे को आंध्रप्रदेश छोड़कर आंध्रप्रदेश एक्सप्रेस से लौट रहे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुखदेव सहि की बल्लभगढ़ स्टेशन पर हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मूलरूप से जालंधर (पंजाब) के रहने वाले 49 वर्षीय सुखदेव सहि कल्याणपुरी पुलिस कालोनी में रहते थे। वे पुलिसकर्मी सुनील कुमार और अभिमन्यु के साथ बच्चे को छोड़ने आंध्रप्रदेश गए थे। तीनों ट्रेन से से दिल्ली लौट रहे थे। सोमवार सुबह करीब पौने सात बजे ट्रेन बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी। वहां अचानक सुखदेव सहि की तबीयत खराब होने लगी। दोनों पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जासं, फरीदाबाद : दिल्ली में मल्लि लावारसि बच्चे को आंध्रप्रदेश छोड़कर आंध्र-प्रदेश एक्सप्रेस से लौट रहे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुखदेव सहि की बल्लभगढ़ स्टेशन पर हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मूलरूप से जालंधर (पंजाब) के रहने वाले 49 वर्षीय सुखदेव सहि कल्याणपुरी पुलिस कालोनी में रहते थे। वे पुलिसकर्मी सुनील कुमार और अभिमन्यु के साथ बच्चे को छोड़ने आंध्रप्रदेश गए थे। तीनों ट्रेन से से दिल्ली लौट रहे थे। सोमवार सुबह करीब पौने सात बजे ट्रेन बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी। वहां अचानक सुखदेव सहि की तबीयत खराब होने लगी। दोनों पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।